



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082020-221210
CG-DL-E-19082020-221210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2020/श्रावण 27, 1942

No. 202]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2020/SHRAVANA 27, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

मामला सं. एसएसआर-10/2020

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए अपेक्षित 'फ्रंट एक्सल बीम' और 'स्टीयरिंग नकल' के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

फा. सं. 7/26/2020-डीजीटीआर.—1. मै. भारत फोर्ज लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए अपेक्षित 'फ्रंट एक्सल बीम' और 'स्टीयरिंग नकल' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और निर्णायक समीक्षा करने तथा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. चीन जन.गण से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच दिनांक 8 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना सं. 14/19/2008-डीजीएडी के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई थी तथा दिनांक 12 अप्रैल, 2010 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 50/2010-सीमाशुल्क के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
4. प्राधिकारी ने दिनांक 13 जून, 2014 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना द्वारा चीन जन गण के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पहली निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत की थी। दिनांक 11 सितंबर, 2015 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/11/2014 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क को आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश की गई थी और इसे दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 49/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 तक लागू है।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान एसएसआर आवेदन में विचाराधीन उत्पाद भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए अपेक्षित 'फ्रंट एक्सल बीम' और 'स्टीयरिंग नकल' है। यह उत्पाद मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के कलपुर्जे और अनुषंगी सामान हैं चाहे वह फोर्ज्ड हों या मशीन द्वारा निर्मित हों।
6. मूल जांच तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पहले की गई प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच के अनुसार उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

विचाराधीन उत्पाद "मध्यम और भारी वाहनों में प्रयुक्त "फ्रंट एक्सल बीम्स (एफएबी) तथा स्टीयरिंग नकल्स (एसके) हैं चाहे फोर्ज्ड हो या मशीन निर्मित। फ्रंट एक्सल बीम सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मद है क्योंकि उस पर पूरे वाहन का भार होता है और वह स्टीयरिंग को अपने स्थान पर भी रखता है। फ्रंट एक्सल बीम का कार्य वाहन के आगे के भार को उठाना, उबड़-खाबड़ सड़कों पर क्षैतिज और उर्ध्वाधर भार को उठाना तथा आरामदायक सफर के लिए स्प्रिंग लीव्स के जरिए एक आधार के रूप में कार्य करना है। स्टीयरिंग नकल एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है जो वाहन के स्टीयरिंग को नियंत्रित करने के लिए आर्मस के जरिए एक्सल बीम में फिट हो सकता है।"

7. चूंकि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद पूर्व में की गई जांच के समान ही रहेगा। संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, के अध्याय-87 और उपशीर्ष 87081090 के अंतर्गत आती है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु भागीदार कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों और अंतिम प्रयोगों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। ये दानों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

9. यह आवेदन मै. भारत फोर्ज लिमिटेड लिमिटेड, जोकि मूल तथा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में याचिकाकर्ता था, द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने मै. रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड से एक समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किया है। आवेदक तथा समर्थक का भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनता है।

10. उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के में दिए गए प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।

पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने बताया है कि चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अंतर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए। समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश ने विचाराधीन उत्पाद की कीमतें या परिकलित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत समेत अन्य देशों को कीमतें न तो आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और न ही सार्वजनिक स्रोत से ऐसी सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। इसके मद्देनजर सामान्य मूल्य को एसजीए व्यय के लिए तथा नियमावली के पैरा 6(8) के अनुसार उत्पादन लागत पर 5 प्रतिशत की दर से तर्कसंगत लाभ के आवश्यक समायोजन के साथ यथा मानकीकृत भारत में उत्पादन लागत को अपनाकर निर्धारित किया गया है।

निर्यात कीमत

12. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा और अन्य पर हुए व्यय को निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए सीआईएफ निर्यात कीमत से घटाया गया है।

पाटन मार्जिन

13. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

14. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन पहले से ही कमजोर है क्योंकि प्रस्तावित पीओआई में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, नकद लाभ और निवेश पर आय में प्रस्तावित अवधि में गिरावट आई है। इसके अलावा, आवेदक ने पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में क्षति की संभावना का दावा किया है और संबद्ध देश में उत्पादकों के पास अधिशेष तथा अप्रयुक्त क्षमताओं, निर्यातोन्मुखीकरण और कम क्षमता उपयोग के संबंध में संबद्ध देश से कीमत कटौती संबंधी सूचना के साथ साथ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

संबद्ध देश

15. इस जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि (पीओआई)

16. जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की होगी। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2016 - 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल - 2018 - 31 मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

17. इस समीक्षा जांच में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समयावधि बढ़ाने की सिफारिश करने वाले दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 49/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी पाटन और क्षति की संभावना का विश्लेषण भी करेंगे।

18. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg11-dgtr@gov.in तथा dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाना चाहिए।
20. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित ईमेल पत्तों पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को लिखित में भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया गया जाए कि उक्त उप नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को देने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को उसके किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा करने की स्थिति में दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। गोपनीय रूप में अंकित एक सैट (शीर्षक, पृष्ठ संख्या, सूची आदि सहित) और अगोपनीय रूप में चिह्नित दूसरा सैट सैट (शीर्षक, पृष्ठ संख्या, सूची आदि सहित)।
27. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि

गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बिद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2020

Case No. SSR-10/2020

Subject : Initiation of Sunset Review Investigation concerning Anti Dumping Duty imposed on imports of “Front Axle Beam and Steering Knuckles meant for heavy and medium commercial vehicles” originating in or exported from China PR .

F. No. 7/26/2020-DGTR.— 1. M/s. Bharat Forge Limited (hereinafter referred to as ‘Applicant’), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “ Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), for sunset review of Anti-Dumping duty imposed on imports of “Front Axle Beam and Steering Knuckles meant for heavy and medium commercial vehicles” (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “Products Under Consideration”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. The Applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and has requested for sunset review, and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.

Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from China PR was initiated by the Authority vide Notification No. 14/19/2008-DGAD dated 8th, December 2008 and vide customs notification No 50/2010-Customs dated 12th April, 2010 definitive anti-dumping duty was imposed for the period of five years.
4. The Authority initiated a first sunset review investigation on subject goods, originating in or exported from China PR vide Initiation Notification dated 13th June, 2014. Vide Final Findings Notification No.15/11/2014-DGAD dated 11th September, 2015, the anti-dumping duty was recommended to be continued for a further period of 5 years and the same were imposed vide Notification No. 49/2015-Customs(ADD) dated 21st October, 2015. The current anti-dumping duties are valid up to 20th October 2020.

Product under Consideration

5. The product under consideration in the present SSR application is “Front Axle Beam and Steering Knuckles meant for heavy and medium commercial vehicles”. The products are parts and accessories of medium and heavy commercial vehicles, whether forged or machined.
6. As per the original investigation and first sunset review investigation carried out by the Designated Authority earlier, product has been defined as under:

“The products under consideration are “Front Axle Beams (FAB) and Steering Knuckles (SK) used in medium and heavy commercial vehicles, whether forged or machined”. Front axle beam is a safety critical item as it carries the load of the vehicle and also keeps the steering in place. The function of the Front axle beam is to carry the front weight of the vehicle, to carry the horizontal and vertical loads on bumpy roads and acts as a cushion through spring leaves for a comfortable ride. The steering knuckle is a very critical component and fits on the axle beam through the arms to control the steering of the vehicle.”

7. The present investigation being a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as in the previously conducted investigation. The subject goods fall under Chapter 87 of the Customs Tariff Act under subheading 87081090. However, the customs classification is only indicative, and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

8. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the participating companies. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry

9. The Application has been filed by M/s. Bharat Forge Limited who was also the petitioner in the original and first SSR investigation. The Applicant has also submitted a support letter from M/s Ramkrishna Forging Limited. The Applicant along with the supporter account for more than 50% of the total production of the subject goods in India.
10. On the basis of information available, the Authority notes that the Application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Likelihood of continuation or recurrence of dumping

Normal Value

11. The Applicant has submitted that China should be considered as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The prices or constructed value of the product under consideration in the appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant nor is this information available with the

Authority from any public source. In view of the same, the normal value has been determined by adopting cost of production in India as normated with due adjustment for SGA expenses and a reasonable profit at the rate of 5% on cost of production in accordance with Para 6(8) of the Rules.

Export Price

12. The export price of subject goods for the subject country has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. The expenses on account of Ocean freight, Marine Insurance and others have been reduced from their CIF export prices to determine the net export price.

Dumping Margin

13. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9A(1)(a) of the Act. There is sufficient prima facie evidence that the normal of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Likelihood of continuation or recurrence of injury

14. The Applicant has claimed that the performance of the domestic industry is already fragile as production, capacity utilization, sales volume, inventories, cash profits and return on investment have deteriorated in the proposed POI. Further, the Applicant has claimed likelihood of injury in the event of cessation of anti-dumping duty, and furnished evidence with regard to significant surplus and unutilized capacities, export orientation, and low capacity utilization of the producers in the subject country, along with information on price undercutting from subject country. The Applicant has claimed that the cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of injury.

Subject Country

15. For the purpose of this investigation, China PR is the subject country.

Period of Investigation

16. The period of investigation (POI) will be from 1st April, 2019 to 31st March, 2020. The injury investigation period will cover the periods 1st April 2016-31st March 2017, 1st April 2017-31st March 2018, 1st April 2018-31st March 2019, and the POI.

Procedure

17. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification no. 49/2015-Customs (ADD) dated 21st October, 2015, recommending extension of anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury.
18. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in.
20. The exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is requested to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

Time Limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority via email at the email addresses mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said sub rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof: one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
27. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

33. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

34. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Special Secy. and Designated Authority